

संख्या-5/2785/XXVII (7)/25-E-42831/2022

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

करवरी

वित्त(वि0आ0-सा0नि0) अनुभाग-07,

देहरादून, दिनांक: 25 जनवरी, 2025।

विषय:- उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना के नियम 6(1) के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागान्तर्गत चिकित्सकों को एस0डी0ए0सी0पी0 की स्वीकृति की तिथि से सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में पुनः वेतन निर्धारण का विकल्प उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागान्तर्गत प्रान्तीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा एवं दन्त शल्यक सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों के लिए लागू एस0डी0ए0सी0पी0 योजनान्तर्गत एस0डी0ए0सी0पी0 की स्वीकृति की तिथि को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना के नियम 6(1) के अन्तर्गत पुनः वेतन निर्धारण हेतु विकल्प उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्ष 2003 बैच के कतिपय चिकित्सा अधिकारियों द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं वित्त विभाग के स्तर पर प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनके 13 वर्ष, 2016 में पूर्ण हो रहे हैं परन्तु उनके द्वारा एस0डी0ए0सी0पी0 की योजना की शर्तों के दृष्टिगत एस0डी0ए0सी0पी0 की स्वीकृति की तिथि को पुनरीक्षित वेतन संरचना में विकल्प का चयन नहीं किया जा सका है। जिससे उनके वेतन का निर्धारण कम हुआ है।

2- उपरोक्त उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत प्रान्तीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन के कम में प्रकरण का समुचित निस्तारण किये जाने हेतु निम्नलिखित तथ्यों का संज्ञान लिया गया :-

- 1 राज्य के पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु मौलिक रूप से नियुक्त प्रान्तीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा एवं दन्त शल्यक सेवा संवर्ग के समस्त कार्यरत चिकित्साधिकारियों को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या-654xxvii-2/ 16-01(120)/ 2008 दिनांक 14 जुलाई, 2016 के द्वारा विशेष डायनमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (SDACP) योजना का लाभ दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से प्रदान किया गया है। इसके अन्तर्गत चिकित्साधिकारियों को उत्तराखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2014 में प्रावधानित पदोन्नति सोपान के दृष्टिगत 04, 09, 13 एवं 20 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर क्रमशः ग्रेड वेतन रू0 6600, 7600, 8700 एवं 8900 के पदोन्नत वेतनमान अनुमन्य किया गया है। एस0डी0ए0सी0पी0 का लाभ प्राप्त किये जाने हेतु पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्र में निर्धारित आवश्यक सेवा क्रमशः 02 वर्ष, 05 वर्ष, 07 वर्ष एवं 09 वर्ष पूर्ण किया जाना भी आवश्यक है। उक्त अवधि में अवकाश की गणना नहीं की जाती है। जो चिकित्सक एस0डी0ए0सी0पी0 हेतु निर्धारित आवश्यक अर्हकारी सेवा अवधि पूर्ण करते हैं, परन्तु

पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्र की अर्हकारी सेवा का प्रतिबन्ध पूर्ण नहीं करते हैं, उनके द्वारा पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्र में आवश्यक सेवा पूर्ण कर लिये जाने पर यह लाभ अनुमन्य होता है। इस सम्बन्ध में वेतन आदि के एरियर का भुगतान उक्तानुसार पात्रता पूर्ण करने की तिथि के तत्काल पश्चात एकमुश्त कर दिया जाता है। शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एस0डी0ए 0सी0पी0 का लाभ दिनांक 01 अप्रैल, 2016 के पूर्व अनुमन्य नहीं हो सकता है।

- II. उत्तराखण्ड सरकारी सेवा वेतन नियम, 2016 में विकल्प चयन का लाभ उस स्थिति में दिया गया है कि जहां सरकारी सेवक को 01 जनवरी, 2016 तथा इन नियमों की अधिसूचना के जारी होने की तिथि के मध्य पदोन्नति, वेतन बैंड/ग्रेड वेतन का उच्चीकरण, समयमान वेतनमान/एस0सी0पी0 के कारण उच्च वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान प्राप्त हुआ है, वह सरकारी सेवक ऐसी पदोन्नति, वेतन बैंड/ग्रेड वेतन का उच्चीकरण अथवा समयमान वेतनमान/एस0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने के विकल्प का चयन कर सकता है। यह भी कि अधिसूचना की तारीख से तीन माह के अंदर विकल्प का चयन किया जा सकता है अथवा यदि विद्यमान वेतन संरचना में कोई संशोधन इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के पश्चातवर्ती किसी आदेश से किया जाता है, तो ऐसे आदेश की तारीख से तीन माह के अंदर उप नियम (2) में उल्लिखित प्राधिकारी के पास पहुंच जाए। अतः स्पष्ट है कि अधिकांश मामलों में उक्त नियमों के आलोक में विकल्प कार्मिक द्वारा ले लिया जाता है क्योंकि सातवें वेतन आयोग की सन्तुति के क्रम में वेतन का निर्धारण एक वर्ष के पश्चात किया गया है।

- III. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागान्तर्गत प्रान्तीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा के वर्ष 2003 बैच के 123 चिकित्सकों में से 93 चिकित्साधिकारियों द्वारा शासनादेश दिनांक-30 दिसम्बर 2016 के नियम 5 व 6(1) के अनुसार, अपने विकल्प का चयन एस0डी0ए0सी0पी0 के स्वीकृत आदेशों के तीन माह के अन्दर किया गया व तदनुसार उनका वेतन निर्धारण हुआ और वेतन आहरित हो रहा है। जबकि 30 चिकित्साधिकारी जो कतिपय कारणों से (विकल्प न देना/न माना जाना) अपने विकल्प का ससमय चयन नहीं कर पाये, उनका वेतन निर्धारण तदनुसार कम हुआ और वेतन आहरण हो रहा है। इससे एक ही बैच के समान स्थिति के विकल्प न देने वाले 30 चिकित्सकों के वेतन में अन्तर आ गया है। साथ ही यह प्रश्न भी उत्पन्न हुआ कि एस0डी0ए0सी0पी0 योजना से आच्छादित चिकित्साधिकारी विकल्प का प्रयोग कब तक कर सकते हैं। इस संबंध में यह स्पष्ट है कि 2003 बैच के 123 चिकित्सा अधिकारियों को 13 वर्ष 2016 में पूरे हो रहे हैं। अतः शासनादेश दिनांक 14 जुलाई, 2016 द्वारा 01 अप्रैल, 2016 से चिकित्साधिकारियों के लिए एस0डी0ए0सी0पी0 योजना किये जाने के क्रम में उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम 2016 के आलोक में उक्त चिकित्साधिकारी वेतन नियम 2016 के नियम 5 व 6(1) के अनुसार, अपने विकल्प का चयन करने की पात्रता रखते हैं।

- IV. एस0डी0ए0सी0पी0 योजना दिनांक 01.04.2016 से लागू होने तथा दुर्गम की सेवा पूर्ण करने की शर्त रखे जाने से ऐसे चिकित्सक जो एस0डी0ए0सी0पी0 हेतु निर्धारित आवश्यक अर्हकारी सेवा अवधि पूर्ण करते हैं, परन्तु पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्र की अर्हकारी सेवा का प्रतिबन्ध पूर्ण नहीं करते हैं, वह SDACP की सुविधा तत्काल प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं। जबकि जिन्होंने दुर्गम में सेवा की है उन्हें SDACP की सुविधा तत्काल प्राप्त हो जाती है। पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्र में आवश्यक सेवा पूरी करने शर्त के दृष्टिगत चिकित्साधिकारियों को एस0डी0ए0सी0पी0 योजना का लाभ समय से न मिल पाने के क्रम में चिकित्सकों को एस0डी0ए0सी0पी0 योजना का लाभ मिलने में और देरी होने के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 04 फरवरी, 2019 द्वारा पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्र की आवश्यक सेवा क्रमशः 02, 05, 07 एवं 09 वर्ष की अर्हकारी सेवा में एक बार शिथिलीकरण (One time Relaxation) प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिससे समस्त चिकित्साधिकारी को एस0डी0ए0सी0पी0 योजना का लाभ वर्ष 2019 में प्राप्त हो गया

है। परन्तु यह पाया गया कि कतिपय चिकित्सक जिन्हें वेतन नियम, 2016 के जारी होने के पश्चात भिन्न-भिन्न वर्षों में एस0डी0ए0सी0पी0 का लाभ प्राप्त हुआ उन्हें इस तथ्य का ज्ञान नहीं था कि यह अब भी सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में दिनांक 01.01.2016 से लागू वेतन मैट्रिक्स में उच्च वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं जिससे उनके द्वारा विकल्प का प्रयोग नहीं किया जा सका अथवा संज्ञान में आने पर विकल्प का प्रयोग किया गया। इससे 30 चिकित्सकों के वेतन का निर्धारण 01 अप्रैल, 2016 से नहीं हो पा रहा है। ध्यातव्य है कि शासनादेश दिनांक 14 जुलाई, 2016 में निर्धारित पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्र में आवश्यक सेवा की शर्त के क्रम में उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के नियम 5 व 6(1) द्वारा वेतन निर्धारण हेतु विकल्प का चयन करने की छूट बिना किसी सीमा के चिकित्साधिकारियों को प्राप्त हो जाती है। जबकि अधिसूचना दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 के जारी होने की तिथि से तीन माह के अंदर ही विकल्प का चयन का प्रावधान है।

- 3- उपरोक्त प्रस्तर-2 पर उल्लिखित तथ्यों के आलोक में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु मौलिक रूप से नियुक्त प्रान्तीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा एवं दन्त शल्यक सेवा संघर्ष के समस्त कार्यरत चिकित्साधिकारियों को उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 अधिसूचना दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 के जारी होने की तिथि से तीन माह के अंदर ही विकल्प का चयन का प्रावधान उपबन्धित होने एवं विशेष डायनमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोजेक्शन (SDACP) योजना की विशेष प्रकृति के दृष्टिगत आपवादिक स्थिति में वेतन नियम, 2016 अधिसूचना दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 के नियम 5 एवं 6 के अनुसार इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन माह के भीतर एक बार पुनः पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने के विकल्प का चयन करने का एक और अवसर इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि दी गयी छूट को किसी भी अन्य मामले में दृष्टांत नहीं माना जायेगा।

Signed by

Dilip Jawalkar

02/02/2025 11:02

सचिव।

संख्या : /XXVII (7)/26-E-42831/2022 तदतिर्नाकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
4. सचिव, विधानसभा सचिवालय, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

Signed by

आशा से,

Ganga Prasad

Date: 25-02-2025 13:16

अपर सचिव।